

एस.आई. पेपर लीक केस के मास्टर माइंड के मुख्य सहयोगी को जमानत मिली

अदालत ने कहा, एस.ओ.जी. परीक्षा केन्द्र पर आरोपी की उपस्थिति साबित नहीं कर पाई

जयपुर, 28 फरवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड यूनिक थांपू के सहयोगी बताए जा रहे शिवरतन मोठ को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस गणेश राम मोपा ने ये आदेश आरोपी को जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि एसओजी ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया, जिससे साबित हो कि याचिकाकर्ता परीक्षा सेंटर पर मौजूद था। अदालत ने कहा कि एसओजी ने याचिकाकर्ता की भूमिका को लेकर सह आरोपी के बयान और परीक्षा के बाद यूनिक थांपू से फोन पर बात करने को लेकर ही जानकारी पेश की है। परीक्षा केन्द्र पर याचिकाकर्ता की ड्यूटी के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं

- राजस्थान हाई कोर्ट ने मास्टर माइंड यूनिक थांपू के मुख्य सहयोगी शिवरतन मोठ को जमानत देते हुए कहा कि परीक्षा केन्द्र पर याचिकाकर्ता की ड्यूटी का कोई सबूत पेश नहीं किया गया।**

- शिवरतन मोठ के वकील ने कहा, याचिकाकर्ता सरकारी कर्मचारी है, गत एक साल से जेल में है। मामले में आरोप पत्र पेश हो चुका है, इसलिए उसे जमानत दी जाए।**

किया गया और न ही ऐसी कोई वीडियोग्राफी पेश की गई, जिससे साबित हो कि याचिकाकर्ता पेपर लीक होने वाले परीक्षा सेंटर पर मौजूद था। इसके अलावा, मामले में पूर्व में ही आरोप पत्र पेश किया जा चुका है। ऐसे में आरोपी को जमानत पर रिहा करना उचित होगा।

याचिकाकर्ता मौके पर मौजूद था। याचिकाकर्ता सरकारी कर्मचारी है और वह करीब एक साल से जेल में है। मामले में आरोप पत्र भी पेश हो चुका है। इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए। वहीं, राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनुराग शर्मा ने कहा कि सह आरोपी राजेश खंडेलवाल की ओर से दी गई जानकारी से पता चलता है कि याचिकाकर्ता पेपर लीक के अपराध में शामिल था। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने भी उस स्थान की पहचान की है, जहां वह मौजूद था। वहीं, कॉल डिटेल से भी याचिकाकर्ता के यूनिक थांपू से संपर्क की बात साबित होती है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।

‘बेटी बचाओ -बेटी पढ़ाओ योजना के 455 करोड़ रु. कहा गए?’

नयी दिल्ली, 28 फरवरी। कांग्रेस ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि मोदी सरकार की महत्वपूर्ण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 455 करोड़ रुपए गायब हो गए हैं और सरकार को इस बारे में देश की बेटियों को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने

- कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केन्द्र सरकार पर आरोप लगाया व कहा कि सरकार देश की बेटियों को जवाब दे।**

आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सूचना के अधिकार आरटीआई के तहत हुए इस खुलासे पता चलता है कि मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लेकर कितना गंभीर है। इससे साबित होता है कि सरकार सिर्फ लुभावने नारे देती है और हकीकत उसके विपरीत होती है। खड़गे ने कहा, "आरटीआई से खुलासा हुआ है कि मोदी सरकार की बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना में 455 करोड़ रुपए गायब हो गए हैं। आरटीआई के ताजे खुलासे से मोदी सरकार के झूठ की कलई एक बार फिर खुल गई है।

तमिलनाडु के मछुआरे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर

- मछुआरे श्रीलंका की नौसेना द्वारा अपने साथियों की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं**

- रामेश्वरम में मछुआरा संघों के नेताओं ने आंदोलनकारियों को संबोधित किया तथा केन्द्र सरकार से समस्या का समाधान करने का आग्रह किया।**

के थंगाचिमदम में अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। रामेश्वरम में विभिन्न मछुआरा संघों के नेताओं ने भूख हड़ताल आंदोलन को संबोधित करते हुए केन्द्र से इस मुद्दे को श्रीलंकाई सरकार के समक्ष उठाने और

त्रिपुरा में 15 बंगलादेशी नागरिक और तीन भारतीय दलाल गिरफ्तार

अगरतला, 28 फरवरी। त्रिपुरा के उनाकोटी जिले में केलाशहर के सीमावर्ती गांवों में घुसपैठ के खिलाफ चलाये गये अभियान में तीन महिलाओं, तीन पुरुषों और सात बच्चों समेत, 13

- इनमें तीन महिलाएं, तीन पुरुष व सात बच्चे शामिल हैं।**

बंगलादेशी नागरिकों तथा तीन भारतीय दलालों को गिरफ्तार किया गया है। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने शुक्रवार को यहां बयान जारी करके कहा कि सभी बंगलादेशी मौलवीबाजार, सुनामगंज, नेत्रगंज, नेत्रेकोना और बारिसल जिलों के निवासी हैं, जबकि भारतीय दलालों की पहचान असम केसिलवर केकाजल दास तथा त्रिपुरा में उनाकोटी केअजीत दास और धलाईके प्रसनजीत देवनाथके रूप में की गयी है। सीमा पार से अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए गुरुवार रात अगरतला रेलवे स्टेशन पर राजकीय रेलवे पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाया गया।

रोहिंग्या बच्चों को सरकारी स्कूलों में प्रवेश दिया जा सकता है

- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया**
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर सरकारी स्कूल रोहिंग्या बच्चों को प्रवेश नहीं देते हैं तो वे हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं।**

से इस मुद्दे के लिए लड़ रहा हूँ और और इस आदेश से सीधे 500 छात्रों को स्कूल में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। बेंच ने कहा कि उन्होंने एक और जनहित याचिका पर इसी तरह का आदेश पहले पारित किया था। कोर्ट ने 12 फरवरी को कहा था कि किसी भी बच्चे को शिक्षा प्रदान करने में भेदभाव नहीं होगा। इस याचिका में केन्द्र और दिल्ली सरकार को रोहिंग्या शरणार्थियों को सरकारी स्कूलों और अस्पतालों तक पहुंच देने का निर्देश देने की मांग

हिमाचल सरकार ने योजनाओं के लिए मंदिरों से पैसा मांगा

हिमाचल सरकार भारी आर्थिक संकट से जूझ रही है, योजनाओं के लिए भी पैसा नहीं है

- भाजपा ने राज्य सरकार की इस बात के लिए कड़ी आलोचना की और कहा, मंदिरों के पैसे से अपनी फ्लैशशिप योजना चलाना चाहती है सरकार।**

के ट्रस्ट भी करेंगे। भाषा एवं संस्कृति विभाग ने मंदिर कमेटियों से जरूरतमंद बच्चों की मदद का आग्रह किया है।

गौरतलब है कि करोड़ों रुपये की आय वाले प्रदेश के 35 बड़े मंदिरों की जिला प्रशासन देखरेख करता है। सरकार की अपील पर उपायुक्तों ने मंदिर न्यास को आर्थिक मदद करने के लिए पत्र जारी कर दिए किए हैं। भाजपा मीडिया प्रभारी करण नंदा ने कहा कि सरकार अब मंदिरों से अपनी सुख आश्रय योजना के लिए पैसे की मांग कर रही है और यह सीधे तौर पर

नहीं बल्कि जिला प्रशासन द्वारा इस डोनेशन की मांग की जा रही है। नंदा ने कहा कि 35 मंदिरों से डोनेशन की मांग की गई है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्यू सरकार एक तरफ सनातन धर्म का विरोध करती है और हिंदू विरोधी बयान देती रहती है। दूसरी तरफ मंदिरों से पैसा लेकर सरकार की फ्लैशशिप योजना चलाना चाह रही है। हिमाचल में सरकारी अधिग्रहण के तहत 35 मंदिर आते हैं। प्रदेश का सबसे सबसे अमीर मंदिर जिला उना में मां चिंतपूर्णी का है। यहाँ मंदिर के खजाने के तहत एक अरब रुपए की बैंक एफडी और एक किंवदंती से अधिक सोना है। प्रदेश में कई बड़े शक्तिपीठ हैं, जिनका संचालन प्रदेश सरकार करती है। बिलासपुर जिले में स्थित शक्तिपीठ नैनादेवी मंदिर के खजाने में 11 करोड़ से अधिक कैश, 58 करोड़ से अधिक की एफडी है। मंदिर के खजाने में 1 किंवदंती 80 किलो सोना है और 72 किंवदंती से ज्यादा चांदी है।

तेलंगाना टनल...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इंस्टीट्यूट (एनजीआरआई) के वैज्ञानिक भी मौके पर पहुंचे हैं। वे ग्रांड पेनेट्रेटिंग रडार (जीपीआर) की मदद से मलबे में दबे मजदूरों ढूँंढने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, किसी भी मजदूर के जीवित मिलने की संभावना बहुत कम लग रही है। नागरकुल्ला के एस्पी वैभव गायकवाड़ ने बताया कि मलबा हटाने और लोहे की छड़ों की कटिंग का काम लगातार जारी है। गुरुवार सुबह से मलबा साफ करने और टनल के पानी को बाहर निकालने का काम चल रहा है। शुक्रवार सुबह 7 बजे एक टीम टनल में गई।(रेस्क्यू ऑपरेशन में आमी, एनडीआरएफ, एंटीआरएफ के अलावा राज्य सरकार की अन्य एजेंसियों के 600 के करीब कर्मी जुटे हैं।

‘अनुसूचित जाति...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नैशनल कमिशन फॉर शिड्यूल्ड कास्ट्स एक संवैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना इस्लियों की गई थी कि यह अनुसूचित जातियों के शोषण के विरूद्ध कवच का काम कर सके तथा उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक हितों की रक्षा कर सके।

‘नकद मानदेय...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ऑफिसर भर्ती-2023 में भाग लिया। इसके पूर्व, उसने सीएमएचओ कोटा के अधीन काम किया था और इसकी एंवज में उसे मानदेय नाद दिया गया। उसे अनुभव प्रमाण पत्र तो जारी कर दिया, लेकिन भर्ती में बोनस अंक का लाभ नहीं दिया गया। इस कारण वह भर्ती की वरीयता सूची से बाहर हो गया। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कक्षा कि केवल मानदेय नाद मिलने के आधार पर उसे भर्ती में बोनस अंक का लाभ देने से मना नहीं किया जा सकता। इसलिए उसे अनुभव के बोनस अंक का लाभ देकर नियुक्ति दी जाए। याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने माना कि काम के बदले नाद मानदेय मिलने पर भी याचिकाकर्ता बोनस अंक प्राप्त करने का अधिकारी है। ऐसे में उसकी नियुक्ति पर विचार किया जाना चाहिए।

‘उत्तर भारत में कई ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

औद्योगिककरण की भरपूर संभावनाएं होने के बाद भी यहां के लोग अवसरों से वंचित महसूस करते हैं। युवाओं में नशे की लत भी एक गंभीर समस्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की भारी मांग है। क्षेत्र का युवा महसूस करता है कि राज्य की दिशा नीति की वजह से वे पड़ोसी राज्यों के युवाओं की तुलना में पिछड़ गए हैं।राज्यपाल के अनुसार, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य के विद्यार्थियों को अपनी भर्जी की भाषा में पढ़ने की सुविधा नहीं दी जानी चाहिए। लगाता है, द्रमुक इसी के इंतजार में थी, पार्टी नेताओं ने राज्यपाल के बयान पर जोरदार पलटवार किया।

अधिकारी को तलब किया है। अदालत ने जांच अधिकारी को 21 मार्च को केस डायरी सहित पेश होकर बताने को कहा है कि उन्होंने इस केस में बाकी आरोपियों के खिलाफ अनुसंधान वीकें क्यों रखा हुआ है। जस्टिस लीकें भारतीयों ने ये आदेश दितलशुश मीणा सहित 21 ग्रामीणों की याचिका पर दिए।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि कुछ आरोपियों के खिलाफ पूर्व में आरोप पत्र पेश किया जा चुका है, जबकि बाकी अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच त्वंचित है। इस पर अदालत ने जांच अधिकारी को हाज़िर होकर इस संबंध में जानकारी पेश कराई

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को बचाने के लिए खोज और बचाव अभियान युद्धस्तर पर लगातार जारी है, हालांकि क्षेत्र में हो रहे छोटे स्तर के लगातार हिमस्खलनों के कारण बचाव कार्य धीमी गति से, लेकिन अधिकतम सतर्कता के साथ किया जा रहा है। सीमा सड़क संयंत्र (जीआरईएफ) जोशीमठ और माणा के बीच की सड़क को साफ करने में जुटा हुआ है, ताकि राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाई जा सके। साथ ही, जोशीमठ से अतिरिक्त चिकित्सा सहायता और संसाधनों को बिना किसी अतिरिक्त विलंब के माणा भेजा जा रहा है।

‘चुनाव के लिए “डीलिमिटेशन” ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विभिन्न गतिविधियों में जुट जाते हैं, जैसे जनता के कल्याण एवं भलाई के लिये, उसकी सहायता करना, हमारी सरकार को उपलब्धियों पर प्रकाश डालने तथा पार्टी के आदर्शों और सिद्धांतों का प्रचार-प्रसार करना।” इस बार अपने जन्मदिन पर, उन्होंने पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को राज्य के सामने खड़ी दो बहुत बड़ी चुनौतियों का स्मरण कराया- “भाषा, जो हमारी लाइफ लाइन है, के लिये लड़ाई तथा परिसीमन, जो हमारा अधिकार है, के लिये संघर्ष करना।” उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया कि वे इस लड़ाई का असली उद्देश्य जनता तक पहुंचाये, क्योंकि लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन राज्य के आत्मसम्मान, सामाजिक न्याय तथा जनकल्याणकारी योजनाओं को सीधा प्रभावित करेगा।

स्टालिन ने जोर देकर कहा, “आप इस संदेश को जनता तक ले जायें आप में से प्रत्येक को अपने राज्य के बचाव के उठना ही चाहिए। हम इस सैद्धांतिक लड़ाई की अगुआई करेंगे तथा पूरे देश को रास्ता दिखायेंगे।

उन्होंने दावा किया कि एकलमता की आवाज़ें कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना तथा अन्य राज्यों से उठ रही हैं तथा इस प्रतिरोध को ध्यान में रखते हुये, केन्द्र ने जोर देते हुये कहा है कि वह राज्यों पर अपनी इच्छा नहीं थोपेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा, “लेकिन, उनकी सारी कार्यवाहियाँ कुछ और ही

उत्तराखंड के ऊंचाई वाले कई इलाकों में बीते 24 घंटों से बर्फबारी हो रही है, जबकि निचले इलाकों में बारिश का दौर जारी है। केदारनाथ धाम, त्रिपुरगीनारायण, तुंगनाथ, चौपाता सहित अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग ने पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी का अॉरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग समेत, अन्य जिलों में बारिश और बर्फबारी की स्थिति अभी बनी रहेगी।

संकेत दे रही हैं।”

स्टालिन ने कहा कि त्रिभाषा-नीति के चलते, तमिलनाडु के बाजिब फंड पहले ही रोक लिये गये हैं। इसी प्रकार, वे दावा कर रहे हैं कि वे तमिलनाडु की संसदीय सीटें कम नहीं करेंगे, लेकिन वे यह आश्वासन देने के लिये तैयार नहीं हैं कि अन्य राज्यों का प्रतिनिधित्व गैर-आनुपातिक तरीके से नहीं बढ़ाया जायेगा। दरअसल, इस मुद्दे पर स्टालिन की अधीतता का कारण केन्द्र की खामोशी है। मोदी सरकार ने इस मुद्दे पर दक्षिणी राज्यों के साथ बात करने की दिशा में अभी तक कोई पहल नहीं की है, जिससे दक्षिण की राजनैतिक पार्टियाँ और सरकारों के साथ विचार-विमर्श करके कोई समाधान तलाश जाये तथा उनकी उन सच्ची चिंताओं का हल निकाला जाये,जो निरंतर अभिव्यक्त हो रही हैं।

हाई कोर्ट ने...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है और उस समय उन्हें मिलने वाला महंगाई भत्ता मूल वेतन के पचास फीसदी से कम था। ऐसे में उन्हें ग्रेज्युटी के तौर पर 25 लाख रुपए नहीं मिले। ऐसे में केन्द्र सरकार के 30 मई, 2024 के आदेश को 7वां वेतन आयोग लागू होने की तिथि से प्रभाव किया जाए। याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने केन्द्र और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।

रामनाथपुरम, 28 फरवरी। तमिलनाडु के मछुआरों को लगातार हिरासत में लिये जाने और श्रीलंकाई नौसेना की ओर से उनकी नावों को जब्त किये जाने के विरोध में सैकड़ों मछुआरों और उनके परिवारों ने शुक्रवार को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी।

मछुआरों ने केन्द्र सरकार से पाक जलडमरूमध्य में मछली पकड़ने के अधिकार के मुद्दे का स्थायी समाधान निकालने की मांग की। रामेश्वरम, पंजन और मंडपम तथा अन्य तटीय बस्तियों की महिलाओं सहित, मछुआरों ने रामेश्वरम

भारत और ई.यू. के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमैंट का ड्राफ्ट तैयार

प्र.मंत्री मोदी और यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के बीच महत्वपूर्ण वार्ता में इस साल के अंत तक एग्रीमैंट पर मुहर लगाने पर सहमति बनी

- अमेरिका और ई.यू. के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए समूचे यूरोपियन आयोग की भारत यात्रा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।**

लिया है। इसके साथ ही इस साल के आखिर तक यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफ.टी.ए.)को भी पूरा करने की बात कही गई है।

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और यूरोप के बीच संपर्क के मुद्दे पर कहा कि भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप आर्थिक गलियारे को आगे ले जाने के लिए टोस कदम उठाए जाएँ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा- “मुझे विश्वास है कि यह गलियारा वैश्विक वाणिज्य, सतत विकास और समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए एक इंजन साबित होगा। भारत और यूरोपीय संघ हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि के महत्व पर सहमत हैं।”

वॉन डेर लेयेन ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ वार्ता के बाद कहा कि हम भारत के साथ यूरोपीय संघ के संबंधों को नयी ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। उन्होंने एक थिंक टैंक को संबोधित करते कहा है कि यूरोपीय संघ जापान और दक्षिण कोरिया के साथ किए गए समझौतों की तरह भारत के साथ भविष्य में “सुरक्षा साझेदारी” की संभावनाएं तलाश रहा है। उन्होंने बताया कि दुनिया किस तरह से खतरों से भरी हुई है। शक्ति को लेकर महाप्रतिस्पर्धा का आधुनिक संस्करण यूरोप और भारत को अपनी साझेदारी के संबंध में “पुन: कल्पना” करने का अवसर देता है। वॉन डेर लेयेन ने कहा है कि भारत अपनी सैन्य आयुति में

^[1] राष्ट्रदूत (एचएयूएफ) के लिए मद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा पहलूद प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालोर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालय: सुभाष, एच.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स: 0141-2373513, कोटा कार्यालय: पलायथा हाऊस, छत्रपति सिंघावा गाँव, कोटा, फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय: कुम्भाना हाऊस, हनुमान हवा, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आश्व भवन, चूगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2413092, फैक्स: 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राधदास भवन, चूगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी1/63, इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर।फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डीनसिटी कार्यालय :- जी1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डीनसिटी। फोन: 230200, 2304000, फैक्स: 07469-230600 सूक्ष्म कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूक, फोन: 256900, 256907, फैक्स: 01562-256908